1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bihar	850	606	244	28.7	770	530	240	31.2
Dvc	695	685	10	1.4	710	700	10	1.4
Orissa	920	910	10	1.1	840	816	24	2.9
West Bengal	1200	1171	29	2.4	1280	1212	68	5.3
Eastern Region	3665	3372	293	8.0	3600	3258	342	9.5
Arunachal Pradesh	13.4	8.6	4.8	35.8	13.1	8.4	4.7	35.9'
Assam	230.9	223.0	7.9	3.4	240.8	225.4	15.4	6.4
Manipur	39	38.6	0.4	1.0	27.6	26.2	1.4	5.1
Meghalaya	39.1	39.1	0	0	30	30	0	0
Mizoram	16.0	16.0	0	0	13.1	11.1	2.0	15.3
Nagaland	16.2	16.2	0	0	13.4	11.1	2.3	17.2
Tripura	34.4	32.5	1.9	5.5	35.0	26.8	8.2	23.4-
North Eastern Region	389.0	374.0	15	3.9	373	339	34.0	9.1
All India	34606	30687	3919	11.3	30695	28400	2295	7.5

हस्तशिल्पियों की दयनीय स्थिति

1168. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को देश में हस्तशिल्पियों की दयनीय स्थिति की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना चलाई गई हैं अथवा बनाए जाने का विचार हैं;

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार देश में भारतीय संस्कृतिक से सम्बन्धित हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने हेतु हस्तशिल्पियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं; और

(ड.) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

श्रम मंत्री और वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, देश में कारीगरों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक जीवन प्रदान करने के लिए सरकार, विभिन्न राज्य हस्तशिल्प निगमोंशीर्ष समितियों स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण, प्रर्दशनी तथा प्रचार, विपणन विकास सहायता, डिजाइन विकास, बर्कशेड-सह-आवास, स्वास्थ्य बीमा, दरिद्रावस्था में सिद्वहस्त शिल्पियों को पेंशन आदि जैसी अनेकों विकासात्मक, संवर्धनात्मक तथा कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करती हैं।

(घ) सरकार, हस्तशिल्प कारीगरों को उनके उत्पादों में वृद्वि करने हेतु ब्याज की उचित रियायती दरों पर, राष्ट्रीयकृत बैंकों, नाबार्ड, सिडबी, आई डी बी आई तथा अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

(ड.) फिलहाल, इन वित्तीय संस्थानों द्वारा हस्तशिल्प कारीगरों को मुहैया करवाए गए ऋण के अलग से आंकड़े नहीं रखे गए हैं। तथापि, अब अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि कारीगरों को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के आंकड़े रखे जाएं।

Steps to Check Violence and Pornography on electronic Media

1169. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the steps taken by USA, Germany, China and some other countries to check violence and pornography on the electronic media (vide the International Herald Tribune, Hong Kong, 29-12-95), (IHT, 2-1-1996 etc.); and

(b) whether Government are contemplating any steps in that direction and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) The said news item relates to the content on computer services and not on the electronic media.

(b) The programme and advertisement code of AIR and Doordarshan, which have been in existence for many years now, contain adequate provisions to prevent the broadcast of programmes/advertisement containing undesirable violence and obscenity.

कुल्लू जिले के बिजली महादेव स्थान पर टी.वी. टावर स्थापित किया जाना

1170. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुल्लू जिले के बिजली महादेव में टी.वी. टावर स्थापित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या उक्त टावर की स्थापना हो गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Programme Transmission Contract to Mumbai Based Firm

1171. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHA JIRAO SHINDE:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Doordarshan has lately awarded a 2 years contract for packaging the daily transmission programme for DD1 and DD2 to a Mumbai based firm; and

(b) if so, the details of the contract and the terms of operation and the modalities norms and rules adopted and observed in the award of the contract so as to ensure transparency in the deal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Captive and Cogcncration Plant

1172. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:
SHRI RAM RATAN RAM:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of captive and cogeneration plants actually set up and started functioning in the country during the last four years;

(b) the names, locations and capacity of these plants; and

(c) the number of such plants likely to be set up during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) In terms of Section 44 of the Electricity (Supply) Act, 1948, approval of only the State Electricity Board of the concerned State is required for setting up of Captive co-generation power plants. The Central Electricity Authority (CEA) does not monitor commissioning/functioning of captive/co-genera-tion power plants.

Justification for Taking a Longer time by the Fifth Pay Commission

1173. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:
SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to the